

# **DAILY** **CURRENT AFFAIRS**

**IN HINDI**

**SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION**

**DATE : 24-11-25**



## The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 24 Nov, 2025

### Edition : International Table of Contents

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page 01</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims</b>                                           | <b>केंद्र सरकार ने कहा, चंडीगढ़ पर विधेयक पेश करने की कोई योजना नहीं है।</b>                                                                                                                             |
| <b>Page 01</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims</b>                                           | <b>सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति की राय फैसले को खारिज नहीं करती : पूर्व सीजेआई</b>                                                                                                                        |
| <b>Page 01 &amp; 04</b><br><b>Syllabus : GS 2 : International Relations &amp; Science and Tech / Prelims</b> | <b>आईबीएसए की बैठक में मोदी ने कहा, 'यूएनएससी में सुधार अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है'</b><br><b>&amp;</b><br><b>प्रधानमंत्री ने दुरुपयोग को रोकने के लिए एआई पर वैश्विक समझौते का आह्वान किया</b> |
| <b>Page 06</b><br><b>Syllabus : GS 3 : Environment</b>                                                       | <b>COP30 ने जीवाश्म ईंधन मुक्त दुनिया के मार्ग के रूप में 'अनुकूलन' पर जोर दिया</b>                                                                                                                      |
| <b>Page 10</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b>                                                     | <b>राज्य पीएससी में सुधार कैसे किया जा सकता है?</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Page 08 : Editorial Analysis</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b>                                | <b>पत्र जीत गया है लेकिन आत्मा नहीं हारी है</b>                                                                                                                                                          |

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले लोकसभा बुलेटिन में सूचीबद्ध इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाना है, जिससे पूर्णकालिक उपराज्यपाल की नियुक्ति हो सके और केंद्र शासित प्रदेश के शासन ढांचे को बिना विधायिका वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा जा सके। चंडीगढ़ विवाद की लंबे समय से चली आ रही और संवेदनशील प्रकृति के कारण पंजाब में इस घोषणा पर कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं।

## No plan to introduce Bill on Chandigarh, says Union govt.

Govt. had listed a Bill that would align Chandigarh with other Union Territories in being administered by the Ministry, but following outrage in Punjab, the Home Ministry now says proposal to 'simplify' law-making process is under 'consideration'

**Vijaita Singh**  
NEW DELHI

**The Chandigarh question**

The Centre hurried to issue a clarification on a Bill that aims to align Chandigarh with other Union Territories without legislatures

- On November 21, the Lok Sabha Bulletin listed the Constitution (131st Amendment) Bill, 2025 among 10 Bills for the Winter Session
- Chandigarh has been a sensitive issue since the Punjab Reorganisation Act of 1966. Currently, the Governor of Punjab serves as its Administrator

**With protests in Punjab, the Ministry issued a clarification**

- Proposal is still under consideration, no final decision yet
- It does not seek to alter Chandigarh's governance or administrative structure
- No Bill will be introduced in the upcoming Winter Session

law-making process for the Union Territory of Chandigarh is still under consideration..."

**No decision on proposal**

"No final decision has been made on this proposal. The proposal in no way seeks to alter Chandigarh's governance or administrative structure, nor does it aim to change the traditional arrangements between Chandigarh and the States of Punjab or Haryana," it said.

"A suitable decision will be made only after adequate consultations with all stakeholders, keeping in mind the interests of Chandigarh. There is no need for concern regarding this matter. The Central Government has no intention of introducing any Bill to this effect in the upcoming Winter Session of Parliament," the Ministry further stated.

Currently, the Governor of Punjab is concurrently the Administrator of Chandigarh, and if the Bill is passed, the Union Territory will be governed by a Lieutenant-Governor.

Congress leader and Rajya Sabha member Jairam Ramesh said that the Parliament Bulletin had listed for "the introduction of a Constitution Amendment Bill to enable the appointment of a full-time L-G for Chandigarh".

"This was immediately and aggressively opposed by the INC and other parties in Punjab whose Governor is also the Administrator of Chandigarh. The Union Home Ministry now says that it has no intention to introduce the Bill in the Winter Session. Yet another example of the Modi Govt's FAST approach to governance - First Announce, Second Think," Mr. Ramesh said.

मुख्य पृष्ठभूमि

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद से चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में, पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं।
- अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को विधायिकाओं के बिना कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

प्रस्ताव ने आक्रोश क्यों पैदा किया?

1. राजनीतिक संवेदनशीलता

- चंडीगढ़ की स्थिति पंजाब और केंद्र के बीच एक मुख्य संघीय मुद्दा है।
- पंजाब अपनी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ पर ऐतिहासिक अधिकार का दावा करता है।
- प्रशासनिक ढांचे को बदलने के किसी भी प्रयास को पंजाब के दावे को कमजोर करने के रूप में माना जाता है।

## 2. केंद्रीकरण की धारणा

- एक अलग एलजी की नियुक्ति को इस प्रकार देखा जा सकता है:
  - पंजाब के पारंपरिक नियंत्रण को कमजोर करना
  - केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्रीय अधिकार बढ़ाना
  - मौजूदा प्रशासनिक परंपराओं में बदलाव

## 3. परामर्श का अभाव

- पंजाब स्थित पार्टियों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम हितधारक परामर्श के बिना उठाया गया है, जो सहकारी संघवाद के खिलाफ है।

## सरकार का स्पष्टीकरण

### गृह मंत्रालय ने कहा:

- यह प्रस्ताव केवल विचाराधीन है।
- कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा।
- यह उपाय केवल "कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने" के लिए है और चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को नहीं बदलता है।
- कोई भी निर्णय हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा।

## व्यापक संवैधानिक और संघीय मुद्दे

### 1. संघीय संतुलन

- चंडीगढ़ शासन भारत के असममित संघवाद को उजागर करता है।
- इसके प्रशासन में बदलाव का केंद्र-राज्य विश्वास पर प्रभाव पड़ सकता है।

### 2. विधायी प्रक्रिया पारदर्शिता

- संसद बुलेटिन में एक प्रस्ताव को सूचीबद्ध करना और बाद में इसे वापस लेना इस बारे में सवाल उठाता है:
  - सरकार की आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता
  - मंत्रालयों के बीच समन्वय
  - राजनीतिक संवेदनशीलता का आकलन

### 3. विपक्ष की आलोचना

- विपक्षी दलों का आरोप है कि 'पहले घोषणा करो, बाद में सोचो' का एक पैटर्न है।
- वे इस कदम को चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित मानते हैं।

## समाप्ति

चंडीगढ़ विधेयक पर विवाद यह दर्शाता है कि कैसे प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक प्रस्ताव भी संघीय संवेदनशीलता और ऐतिहासिक दावों को छूते समय तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकते हैं। विधेयक को रोकने का केंद्र का निर्णय केंद्र शासित प्रदेशों और साझा प्रशासनिक स्थानों से संबंधित संवैधानिक संशोधनों में परामर्श, पारदर्शिता और सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करता है।

### UPSC Prelims Practice Question

**प्रश्न:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रपति को दिल्ली और चंडीगढ़ सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
2. अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए विनियमों में संसद के अधिनियम के समान बल है।
3. अनुच्छेद 240 केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है जहां विधायिका नहीं है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर : a)**

### UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** एक साझा राजधानी के रूप में चंडीगढ़ की स्थिति के पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ की व्याख्या करें और विश्लेषण करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक परिवर्तन अंतर-राज्यीय राजनीतिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।  
(150 शब्द)

हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने स्पष्ट किया कि विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों के लिए समयसीमा के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति की राय तमिलनाडु के राज्यपाल के पहले के फैसले को खारिज नहीं करती है। इसके बजाय, यह केवल कानून को स्पष्ट करता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विधायी प्रक्रियाओं में राज्यपालों की भूमिका को लेकर केंद्र-राज्य में तनाव जारी है।

## पृष्ठभूमि: समस्या का कारण क्या था?

### 1. 8 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट का फैसला (तमिलनाडु गवर्नर केस)

- माना गया कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर बिलों को मंजूरी देनी होगी, ऐसा न करने पर विधेयक को "सहमति प्राप्त हुई मानी जाएगी।

### 2. राष्ट्रपति का संदर्भ

- केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति संदर्भ) के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टता मांगी थी।
- 20 नवंबर को, सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक सलाहकार राय दी:
  - राज्यपालों को एक सख्त समयसीमा का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  - उन्हें "उचित अवधि" के भीतर कार्य करना चाहिए।
  - "उचित अवधि" स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।

## सीजेआई गवई ने क्या स्पष्ट किया?

### 1. राष्ट्रपति का संदर्भ किसी निर्णय को खारिज नहीं करता है

- यह केवल कानून को स्पष्ट करता है।
- एक निर्णय तब तक बाध्यकारी रहता है जब तक कि भविष्य के मामले में खारिज न कर दिया जाए।
- सलाहकार राय यह इंगित कर सकती है कि कानून की पहले की समझ "सही नहीं थी," लेकिन यह निर्णय को रद्द नहीं करती है।

### 2. न्यायालय संविधान में मौजूद नहीं होने वाली समय-सीमा नहीं डाल सकता है

- यदि एक समयसीमा की आवश्यकता होती है, तो संविधान में संशोधन करना या कानून बनाना संसद की भूमिका है।
- न्यायपालिका "बेंच से कानून नहीं बना सकती।

### 3. राज्यपाल की शक्तियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण

- सख्त समयसीमा हटा दी गई।
- लेकिन राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक नहीं बैठ सकते।

**SC's Presidential Reference opinion does not overrule a judgment: ex-CJI**

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

Chief Justice of India B.R. Gavai, who retired from the post on Sunday, said the Presidential Reference opinion against tying Governors to timelines was not intended to shift the burden back on the States to run pillar-to-post to get their recalcitrant Governors to pass pending Bills on time.

"If the Constitution does not provide for a timeline, we [judiciary] cannot read something that is not there. It is for the Parliament to do that," he said.

He explained that an opinion given in a Presidential Reference did not overrule a judgment but only clarified the law.

"In a Presidential Reference, we cannot overrule a judgment, but we can lay down the law, and while laying down the law, we can observe that the law laid down in a particular manner [in a judgment] is not correct," he said.

**T.N. Governor case**  
The Presidential Reference was triggered by a judgment in the Tamil Nadu Governor case on April 8, which broke the silence in the Constitution and held that Bills must be cleared by the Governors and President in three months or they would be "deemed" to have got assent.

On November 20, a five-judge Bench led by Chief Justice Gavai, in its advisory opinion, contradicted the April 8 judgment and concluded that Governors and the President cannot be forced to follow a timeline. They need to act only within a "reasonable period".

The Bench, however, did not specify the term "reasonable period" in its opinion.

**Limited judicial review**  
"We have only relaxed the timeline. At the same time, we have balanced it by saying the Governor cannot sit on a Bill endlessly. We have also provided for a limited judicial review based on the facts and circumstances of each case. You cannot have a straitjacket formula that in every Bill, if assent is not granted, it would be deemed to have been passed. In a routine Bill, one month is sufficient for a Governor to clear it. However, in Bills concerning internal or external emergency, a Governor may not be able to take a call in a month. He may take three or four months," he said.

To a question whether Justice B.V. Nagarathna's dissent to a Supreme Court proposal to elevate Justice Vipul Manubhai Pancholi had any merit, the former Chief Justice said that "if it had, the four other judges on the collegium would not have agreed to the proposal".

- सीमित न्यायिक समीक्षा को मामला-दर-मामला अनुचित देरी की जांच करने की अनुमति दी गई।
- "उचित अवधि" इस पर निर्भर करता है:
  - अत्यावश्यकता
  - विधेयक की प्रकृति
  - सुरक्षा या आपात स्थिति से संबंधित चिंताएं
  - साधारण बिलों को "एक महीने" में निपटाया जा सकता है

## संवैधानिक कोण

### शामिल लेख

- अनुच्छेद 200 – राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प
- अनुच्छेद 201 – कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका
- अनुच्छेद 143 - राष्ट्रपति का संदर्भ
- तर्कसंगतता का सिद्धांत - न्यायिक व्याख्या के माध्यम से आयात किया गया
- संविधान में कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं है

### संघवाद प्रभाव

- यह मामला केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव को दर्शाता है, विशेष रूप से:
  - राज्यपाल पद का राजनीतिकरण
  - सहमति शक्तियों का शस्त्रीकरण
  - राज्य विधानसभाओं को प्रभावित करने वाली देरी की रणनीति

## सलाहकार राय के निहितार्थ

### 1. राज्यपालों को अधिक शक्ति?

- सख्त समयसीमा हटाने से विवेक बढ़ सकता है।
- "उचित समय" में अस्पष्टता आगे संघर्ष पैदा कर सकती है।

### 2. सीमित न्यायपालिका निरीक्षण

- अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं जब देरी स्पष्ट रूप से अनुचित होती है।
- लेकिन वे एक समान समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते।

### 3. संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करता है

- संयम पर प्रकाश डालता है: न्यायपालिका संविधान में शब्दों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है।
- न्यायिक सुधार की नहीं, बल्कि विधायी स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया।

### 4. राज्यों को अभी भी देरी का सामना करना पड़ सकता है

- निश्चित समय-सीमा के बिना, राज्य विधेयकों पर अनिश्चितकालीन बैठक के माध्यम से कार्यकारी बाधा का अनुभव करना जारी रख सकते हैं।

## सहकर्मियों के मतभेदों पर पूर्व सीजेआई का दृष्टिकोण

- न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति के संबंध में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति पर, उन्होंने टिप्पणी की:
  - अगर असहमति में दम होता, तो कॉलेजियम के चार अन्य न्यायाधीश सहमत नहीं होते।
- यह नियुक्तियों पर न्यायपालिका के भीतर आंतरिक जांच को दर्शाता है।

## समाप्ति

पूर्व सीजेआई की टिप्पणी एक निर्णय और एक राष्ट्रपति संदर्भ सलाहकार राय के बीच सूक्ष्म अंतर को रेखांकित करती है। जबकि नई राय सख्त समयबद्ध आवश्यकता को शिथिल करती है, यह राज्यपालों को जवाबदेही से पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है। इसके बजाय, यह सीमित न्यायिक समीक्षा द्वारा समर्थित एक लचीला, मामला-विशिष्ट ढांचा बनाता है। संघवाद और राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका में निहित बड़ी बहस अनसुलझी है और भारत में केंद्र-राज्य संबंधों को आकार दे रही है।

## UPSC Prelims Practice Question

**प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।
2. राष्ट्रपति संदर्भ की राय सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले को रद्द कर सकती है।
3. सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के संदर्भ का जवाब देने से इनकार कर सकता है।

**इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: b)**

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न : क्या राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बार-बार होने वाले विवाद संविधान में एक संरचनात्मक दोष का संकेत देते हैं, या वे कार्यालय के राजनीतिक दुरुपयोग का परिणाम हैं? हाल के उदाहरणों के साथ समझाइए। (250 शब्द)**

जोहान्सबर्ग में आईबीएसए लीडर्स समिट और जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप वैश्विक शासन प्रणालियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत के मजबूत प्रयास और उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के मानव-केंद्रित और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ में, ये भाषण भारत के बड़े रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं: ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना, वैश्विक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करना और वैश्विक प्रौद्योगिकी मानदंडों को आकार देना।

## Part I – IBSA Summit: UNSC Reform as a Necessity

### UNSC reforms no longer an option but a necessity: Modi at IBSA meet

Press Trust of India  
JOHANNESBURG

Prime Minister Narendra Modi on Sunday said reform of the United Nations Security Council (UNSC) was no longer an option but a necessity, and asserted that the India-Brazil-South Africa troika should send a clear message for changes to institutions of global governance.

Addressing the India-Brazil-South Africa (IBSA) leaders summit here, Mr. Modi said that at a time when the world appeared fragmented and divided, the IBSA could provide a message of unity, cooperation, and humanity.

He proposed institutionalising the IBSA NSA-level meeting to strengthen security cooperation among the three countries.

"In the fight against terrorism, we must move forward in close coordination. There is no place for any double standards on such a serious issue," Mr. Modi said at the meeting attended by South African President Cyril Ramaphosa and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva.

The Prime Minister said the IBSA was not just a group of three countries but an important platform connecting three continents, three major democratic nations, and three major economies.

Highlighting technology's crucial role in ensuring human-centric development, the Prime Minister proposed establishing an IBSA Digital Innovation Alliance to facilitate the sharing of digital public infrastructure such as unified payments interface (UPI), health plat-

forms such as CoWIN, cybersecurity frameworks and women-led tech initiatives among the three countries.

"Timely meet" Appreciating the IBSA Fund's work in supporting projects across 40 coun-



Prime Minister Narendra Modi with South African President Cyril Ramaphosa (left) and Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva. ANI

tries in sectors such as education, health, women empowerment and solar energy, Mr. Modi proposed the IBSA Fund for Climate Resilient Agriculture to further advance South-South cooperation.

He said the IBSA meeting was timely as it coincided with the first G20 Summit on African soil and marked the culmination of four consecutive G20 presidencies by Global South countries, out of which the last three were by the IBSA members.

This has resulted in several important initiatives focused on human-centric development, multilateral reform and sustainable growth, he said.

Mr. Modi also invited IBSA leaders to the AI Impact Summit to be held in India next year, even as he emphasised the grouping's potential to contribute to the development of safe, trustworthy and human-centric AI norms.

The Prime Minister said the IBSA can complement each other's development and become an example for sustainable growth. He highlighted cooperation opportunities in areas such as millets, natural farming, disaster resilience, green energy, traditional medicine and health security.

"No ordinary grouping" Later, in a post on social media, Mr. Modi said the IBSA reflects "our enduring commitment to strengthening the voice and aspirations of the Global South. IBSA is no ordinary grouping."

"Ours is a bond that is heartfelt, carrying with it diversity, shared values and shared aspirations. All three IBSA nations have held the G20 Presidency in the last three years and have used this opportunity to further the human-centric agenda," he said.

The IBSA grouping focuses on promoting South-South cooperation, pushing for reforms in global governance systems and enhancing collaboration among developing nations.

In September, External Affairs Minister S. Jaishankar, Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, and the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities of South Africa Sindisiwe Chikunga had met on the sidelines of the annual United Nations General Assembly session in New York.

The Ministers had called for an ambitious, comprehensive and profound reform of the United Nations, particularly the UN Security Council, to adapt it to contemporary geopolitical realities and address new global challenges.

RELATED REPORT ON  
» PAGE 4

## 1. UNSC सुधार का आह्वान

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यक हैं। उनका मुख्य तर्क:

- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य खंडित और संस्थागत रूप से पुराना है।
- आईबीएसए को वैश्विक शासन के पुनर्गठन के लिए एक स्पष्ट और एकीकृत संदेश भेजना चाहिए।

## 2. IBSA का रणनीतिक महत्व

मोदी ने आईबीएसए को इस प्रकार चित्रित किया:

- तीन महाद्वीपों (एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका) को जोड़ने वाला एक मंच
- तीन प्रमुख लोकतंत्र
- तीन उभरती अर्थव्यवस्थाएं
- ग्लोबल साउथ की एक मुख्य आवाज

## 3. सुरक्षा और रक्षा समन्वय को मजबूत करना

उन्होंने प्रस्ताव रखा:

- आईबीएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बैठक को संस्थागत बनाना।

- दोहरे मानकों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाया गया।

4. प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग

मोदी ने दो प्रमुख प्रस्ताव दिए:

1. आईबीएसए डिजिटल इनोवेशन एलायंस
  - डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करना (UPI, CoWIN)
  - साइबर सुरक्षा ढांचे
  - महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहलों के लिए समर्थन
2. जलवायु-लचीली कृषि के लिए आईबीएसए फंड
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग का विस्तार
  - कृषि, पर्यावरण और स्थिरता पर ध्यान दें

5. जी-20 अध्यक्षताओं का अभिसरण

- आईबीएसए की वर्तमान बैठक अफ्रीकी धरती पर पहले जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ मेल खा रही है।
- पिछले तीन जी-20 अध्यक्षताएं (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) आईबीएसए सदस्यों द्वारा आयोजित की गई हैं।
- यह ग्लोबल साउथ की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को दर्शाता है।

Part II – G-20 Summit: Global Compact on AI

### PM calls for global compact on AI to prevent misuse

The pact must be based on certain core principles like effective human oversight, safety-by-design, transparency, and restrictions on AI use in deepfakes, crime, terror activities, says Modi at G-20

**Press Trust of India**  
JOHANNESBURG

**P**hile Minister Narendra Modi on Sunday called for a global compact to prevent misuse of artificial intelligence (AI), and made a strong pitch for critical technologies to be “human-centric”, instead of “finance-centric”.

Addressing the third session of the G-20 Summit on the topic “A fair and a just future for all – critical minerals; decent work; artificial intelligence”, Mr. Modi said technology applications should be “global” rather than “national” and based on “open source” rather than “exclusive models”. Mr. Modi said that this vision had been integrated into India’s technology ecosystem, and it had resulted in significant benefits, be it in space applications, AI or digital payments, where it is a world leader.

“We must all ensure that AI is used for global good and its misuse is prevented. To do this, we must create a global compact on AI, based on certain core principles, including effective human oversight, safety-by-design, transparency, and strict restrictions on the use of AI in deepfakes, crime, and terror activities,” Mr. Modi said.

The Prime Minister said AI systems that impact human life, security, or public trust must be “responsible and auditable”. “And most importantly, AI should enhance human capabilities, but the ultimate responsibility for decision-making always remains with humans,” he added. He said that in this age of AI, the approach must rapidly shift from “jobs of today” to “capabilities of tomorrow”. “Unlocking talent mobility is essential for rapid innovation. We made progress on this topic at the Delhi G20. We hope that in the next few years, the G-20 will develop a global framework for talent mobility,” he said.

Mr. Modi said that under the India-AI Mission, accessible high-performance computing capacity was being built with the aim of ensuring that AI benefits reached everyone.

The Prime Minister said India would be hosting the AI Impact Summit in February 2026 with the theme “Sarvajanam Hitaya, Sarvajanam Sukhaya” [welfare for all, happiness for all]. He articulated India’s message for global well-being, asserting that it stood for development that is sustainable, trade that is trusted, finance that is fair, and progress in which everyone prospers.



**Laying out a road map:** Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during a session at the G-20 Summit held in Johannesburg on Sunday. PTI

## 1. एआई के दुरुपयोग को रोकना

जी-20 सत्र में, पीएम मोदी ने एआई पर एक वैश्विक कॉम्पैक्ट का आह्वान किया, जिसमें रोकथाम की आवश्यकता पर बल दिया गया:

- डीपफेक
- साइबर अपराध
- एआई का आतंकवादी उपयोग
- जनता के विश्वास का क्षरण

मूल सिद्धांत प्रस्तावित:

- मानवीय निरीक्षण
- सुरक्षा-दर-डिज़ाइन
- पारदर्शिता मानक
- अवैध उपयोग पर प्रतिबंध

## 2. मानव-केंद्रित बनाम वित्त-केंद्रित प्रौद्योगिकी

मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रौद्योगिकी का लक्ष्य निम्नलिखित होना चाहिए:

- मानव विकास
- नैतिक परिनियोजन
- समावेशी और वैश्विक पहुंच

के लिए नहीं:

- लाभ-केंद्रित या विशिष्ट मॉडल: यह डिजिटल गवर्नेंस में भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है - यूपीआई, कोविन, जन धन और आधार-आधारित डिजिटल इकोसिस्टम।

## 3. जवाबदेही सुनिश्चित करना

मोदी ने जोर देकर कहा:

- सुरक्षा या सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करने वाले एआई सिस्टम जिम्मेदार और ऑडिट योग्य होने चाहिए।
- मनुष्य को अंतिम निर्णय लेने के अधिकार को बनाए रखना चाहिए।

## 4. भविष्य की नौकरियों की तैयारी

उन्होंने जोर दिया:

- "आज की नौकरियों" से "कल की क्षमताओं" पर ध्यान केंद्रित करना।
- वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता को अनलॉक करना, जी-20 फ्रेमवर्क के जल्द ही उभरने की उम्मीदों के साथ।

## 5. भारत-एआई मिशन और वैश्विक नेतृत्व

- भारत एआई समावेशन के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता विकसित कर रहा है।

- मोदी ने "सर्वजनम हिताय, सर्वजनम सुखाय" विषय के तहत भारत के आगामी एआई इम्पैक्ट समिट (2026) की घोषणा की।

## **भू-राजनीतिक महत्व**

### **1. ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत**

आईबीएसए और बार-बार जी-20 सक्रियता के माध्यम से, भारत खुद को इस प्रकार स्थापित कर रहा है:

- विकासशील देशों का प्रतिनिधि
- संस्थागत परिवर्तन की मांग करने वाला एक सुधारवादी
- विश्व स्तर पर तकनीकी नैतिकता को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी

### **2. UNSC सुधार कथा मजबूत होती है**

भारत का तर्क:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकताओं को दर्शाती है, न कि समकालीन भू-राजनीति को।
- ग्लोबल साउथ का स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- आईबीएसए का संयुक्त धक्का राजनयिक वजन को मजबूत करता है।

### **3. भविष्य के वैश्विक एजेंडे के रूप में एआई शासन**

भारत निम्नलिखित पर जोर दे रहा है:

- एक सार्वभौमिक, नियम-आधारित एआई प्रणाली
- नैतिक सुरक्षा उपाय
- समान नवाचार के अवसर

इससे एक जिम्मेदार तकनीकी शक्ति के रूप में भारत की छवि मजबूत होती है।

## **समाप्ति**

आईबीएसए और जी-20 दोनों मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान भारत की दोहरी कूटनीतिक रणनीति को उजागर करते हैं: यूएनएससी जैसे वैश्विक राजनीतिक संस्थानों का आधुनिकीकरण करना और नैतिक और समावेशी मानदंडों के साथ उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को आकार देना। साथ में, ये पहल न केवल एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा पर जोर देती हैं, बल्कि 21वीं सदी में वैश्विक शासन के लिए एक आदर्श भी स्थापित करती हैं।

**UPSC Prelims Practice Question**

**प्रश्न: IBSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. IBSA एक त्रिपक्षीय मंच है जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
2. आईबीएसए ब्रिक्स का एक हिस्सा है और ब्रिक्स ढांचे के तहत कार्य करता है।
3. आईबीएसए के प्रमुख उद्देश्यों में से एक दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है।

**कौन से कथन सही हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: b)**

**UPSC Mains Practice Question**

**प्रश्न :** यूएनएससी सुधार अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में आईबीएसए की स्थिति के संदर्भ में चर्चा करें। **(150 शब्द)**

ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 देशों द्वारा "जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण" की आवश्यकता को स्वीकार करने के साथ समाप्त हुआ, लेकिन अंतिम मुतिराओ (एक साथ आना) समझौते ने जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा पर अधिक जोर दिया। शिखर सम्मेलन ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर स्थायी वैचारिक विभाजन को प्रतिबिंबित किया और जलवायु-कमजोर देशों के लिए अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला।

## COP30 stresses 'adaptation' as path to fossil fuel-free world

Countries have called to 'at least triple' adaptation finance by 2035 and to hold a systematic dialogue, with existing UN trade forums on ensuring that measures to combat climate change do not impede trade or growth in developing countries

NEWS ANALYSIS

Jacob Koshy  
NEW DELHI

The deliberations at COP30, which concluded in Brazil on Saturday, underlined that while countries agreed upon transitioning away from fossil fuel, more emphasis ought to be laid on adapting to climate change rather than defining road maps to end use of fossil fuels.

As the text of the consensus, called the Mutirão (coming together) agreement, says, countries have agreed to establish a two-year "work programme" on climate finance; called for efforts to "at least triple" adaptation finance by 2035. They have agreed to a systematic dialogue with participation from United Nations' trade forums – for example, International Trade Centre, the UN Conference on Trade and Development and the World Trade Organization – on how measures to combat climate change should not impede trade and growth of developing countries.

Climate finance refers to money that must be dis-



COP PRESIDENT

André Corrêa do Lago, COP30 President, sits as Simon Stiell, UN climate chief, left, speaks with other UN officials during a plenary session in Belem, Brazil, on Saturday. AP

bursed by developed countries to developing ones. The aim of COPs (Conference of Parties) has been on delivering climate finance evenly for mitigation (avoiding fossil fuel projects and funding renewable energy) and adaptation (building infrastructure to better shield against climate change, investing in resilient agriculture, and so on). However, mitigation projects are generally more business-friendly and have garnered more attention.

"While the adaptation finance decision wasn't what developing countries wanted, it helps ensure that funding for adaptation will continue to grow... Even though the deadline is a decade away, developed countries can't be complacent and must immediately get to work, scaling up adaptation support. Having this goal within the framework of the NCQG means that developed countries take the lead, with other countries encouraged to contribute voluntarily," Joe Thwaites, International Climate Finance Director, Natural Resources Defense Council, a global think tank, said in a statement. New Collec-

tive Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) refers to an agreement in COP29, Baku, by developed countries to mobilise \$300 billion annually by 2035 and work towards expanding it to \$1.3 trillion annually from all sources.

**Ideological divide**  
The deliberations at the COP through the years have often been framed as a contest between two ideological blocs – those that want hard targets and road maps on phasing out of fossil fuels and those that resist them.

India, for instance, in the final leg of deliberations on Saturday, expressed "satisfaction with major outcomes" of COP30 such as a Just Transition Mechanism (JTM) and for "delivering the space" to discuss Unilateral Trade-restrictive Climate Measures. "These issues cannot continue to be brushed under the carpet. The Parties have made a beginning here to reverse this trend," a statement by a group of largely developing countries noted. The JTM refers to a process whereby labour systems can be made to adapt to a future away from fossil fuel in a way that promotes justice and equity.

The COP30 Mutirão agreement has no mention of 'fossil fuels' or a road map to end their use – meaning they are not part of the consensus agreement. COP President André Lago's commitment to creating two road maps – one on halting and reversing deforestation and another on transitioning away from fossil fuels in a just, orderly, and equitable manner, is viewed as a placatory measure towards the European Union and countries demanding an end to use of fossil fuels.

COP30 के प्रमुख परिणाम

1. अनुकूलन पर ज़ोर

- देश 2035 तक अनुकूलन वित्त को "कम से कम तिगुना" करने पर सहमत हुए।
- जलवायु वित्त पर दो साल के कार्य कार्यक्रम की स्थापना।
- यह मान्यता कि अनुकूलन (लचीलापन-निर्माण, जलवायु-प्रूफ बुनियादी ढांचा, कृषि) को शमन की तुलना में अधिक वैश्विक ध्यान देने की आवश्यकता है।

## अनुकूलन क्यों?

- विकासशील देशों को असमान रूप से सामना करना पड़ता है:
  - चरम मौसम क्षति
  - कृषि नुकसान
  - तटीय भेद्यता
- अनुकूलन को ऐतिहासिक रूप से कम वित्त पोषित किया गया है क्योंकि शमन अधिक व्यवसाय के अनुकूल है।

## 2. जलवायु उपायों और व्यापार पर व्यवस्थित संवाद

- COP30 ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख व्यापार निकायों के साथ बातचीत का आह्वान किया:
  - आईटीसी, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ
- उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि CBAM, कार्बन कर और आपूर्ति-श्रृंखला मानक जैसी जलवायु नीतियां विकासशील देशों के व्यापार या विकास में बाधा न डालें।
- यह संबोधित करने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है:
  - एकतरफा व्यापार-प्रतिबंधात्मक जलवायु उपाय
  - वैश्विक जलवायु असमानताएं

## 3. जलवायु वित्त: एक मुख्य स्तंभ

- शिखर सम्मेलन ने NCQG (न्यू क्लेक्टिव क्वांटिफाइड गोल) की पुष्टि की:
  - 2035 तक सालाना 300 बिलियन डॉलर
  - प्रति वर्ष \$1.3 ट्रिलियन तक का लक्ष्य
- विकसित देशों को नेतृत्व करने की उम्मीद है; अन्य लोग स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं।

### विकासशील देशों की चिंताएँ

- अनुकूलन वित्त प्रतिबद्धताएं अभी भी कम हैं।
- कार्यान्वयन की समय सीमा दीर्घकालिक (10+ वर्ष) है, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है।
- पूर्वानुमानित, रियायती और अनुदान-आधारित वित्त की आवश्यकता।

## 4. वैचारिक विभाजन: जीवाश्म ईंधन चरण-आउट बनाम इक्विटी के लिए स्थान

COP30 सर्वसम्मति पाठ में "जीवाश्म ईंधन" का कोई उल्लेख नहीं है

- समझौते में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए लक्ष्य या समयसीमा शामिल नहीं है।
- विकासशील देशों के प्रतिरोध को दर्शाता है जो:
  - जीवाश्म ईंधन राजस्व पर निर्भर करता है
  - विकास के लिए ऊर्जा पहुंच की आवश्यकता है
  - संक्रमण मार्गों में निष्पक्षता और समानता की मांग करें

### भारत की स्थिति

- स्वागत:
  - जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म (JTM)
  - अनुचित व्यापार-प्रतिबंधात्मक जलवायु उपायों पर चर्चा करने के लिए मंच
- इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन न्यायसंगत, व्यवस्थित, न्यायसंगत और विकास की जरूरतों पर विचार करना चाहिए।

### 5. सीओपी अध्यक्ष के अलग रोड मैप (आम सहमति का हिस्सा नहीं)

मजबूत कार्रवाई की मांग करने वाले देशों को खुश करने के लिए, सीओपी प्रेसीडेंसी ने दो गैर-बाध्यकारी रोड मैप की घोषणा की:

1. वनों की कटाई को रोकना और उलटना
2. जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण

ये राजनीतिक संतुलन उपकरण के रूप में काम करते हैं लेकिन अंतिम समझौते में कानूनी वजन की कमी है।

### समाप्ति

COP30 एक बदलते जलवायु कूटनीति परिदृश्य को रेखांकित करता है जहां ग्लोबल साउथ के लिए अनुकूलन, निष्पक्षता और विकास का स्थान केंद्र स्तर पर है। जबकि शमन आवश्यक बना हुआ है, अंतिम पाठ में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्यों की अनुपस्थिति लगातार भू-राजनीतिक विभाजन को प्रकट करती है। परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी सार्थक जलवायु परिवर्तन को विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इक्विटी, वित्त और विकास की जरूरतों के साथ जलवायु महत्वाकांक्षा को संतुलित करना चाहिए।

### UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** COP30 ने वैश्विक जलवायु कथा को जीवाश्म ईंधन चरण-आउट से जलवायु अनुकूलन में स्थानांतरित कर दिया है। विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए इस बदलाव के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)

राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) राज्य सिविल सेवाओं के लिए योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए संवैधानिक निकाय हैं। हालांकि, बार-बार विवादों, परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक, मुकदमेबाजी और देरी ने उनकी विश्वसनीयता को कम कर दिया है। जैसा कि तेलंगाना में राज्य पीएससी अध्यक्षों का 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता तत्काल हो गई है।

### How can State PSCs be reformed?

How did the Montagu Chelmsford report lead to the establishment of present-day Public Service Commissions? What is the role of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions? Is a periodical review of the examination syllabi necessary?

**EXPLAINER**

Gopikrishna, V

**The story so far**

The 2025 national conference of chairpersons of the State Public Service Commissions (PSCs) is being hosted by the Telangana State Public Service Commission on December 19 and 20. Every year, whenever State PSCs conduct examinations for recruitment, they are mired in one controversy or the other. Aspirants often have to seek judicial recourse, due to which the entire process is derailed, leading to a 'trust deficit'. This is an outcome of systemic lapses, both structural and procedural, which exist in almost all State PSCs. This conference would be an apt occasion to discuss such issues and more.

**What is the history of PSCs?**

The PSCs in India are a product of India's struggle for independence. The entry of Indians into the civil services on the sole criterion of merit was embedded in the demand for 'self-rule'. The Montagu Chelmsford report accepted the demand and proposed a permanent office free from political influence to regulate service matters. The first Public Service Commission for the Union was formed in 1926. Later the Government of India Act, 1935 provided for the establishment of one PSC for each province. These provisions were continued by the framers of the Constitution, and so today we have a Union Public Service Commission (UPSC) and PSCs in each State to primarily serve the needs of recruitment.

**How are these commissions structured?**

The UPSC functions in a relatively politically sterile environment. The members are appointed based on merit and rich prior experience in public affairs. Moreover, representation of members from all zones of the country is ensured. While the Constitution does not mention minimum age or qualifications, most of the appointed members are at least above the age of 55, and enjoy a reputation of being apolitical. On the other hand, State PSCs operate in a politically onerous environment and the proverbial 'spoils system' is visible in the appointment process. The conventional requirements of minimum age, qualifications and public experience are given a short shrift.

The Union government has vast manpower needs. This is matched by financial resources to meet the retirement obligations of the superannuated and the remunerative needs of fresh entrants. It has also created a dedicated ministry, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in 1985, to formulate all policies in the field of personnel management. This ensures regular declaration of vacancies by the government enabling the UPSC to notify, conduct and declare the results of the examinations conducted by it with regularity and precision.

In contrast, the manpower needs of the States are limited and not planned. Often, they lack the financial resources to meet the retirement and recruitment obligations of their employees leading to extension of the superannuation age and postponement of recruitment. Most State governments do not have a dedicated Ministry of Personnel. And therefore, vacancies are not notified regularly by the government which effectively means that State PSCs are not required to conduct



**THE GIST**

The entry of Indians into the civil services on the sole criterion of merit was embedded in the demand for 'self rule'.

The manpower needs of the States are limited and not planned. Often, they lack the financial resources to meet the retirement and recruitment obligations of their employees leading to extension of the superannuation age and postponement of recruitment.

State PSCs do not appoint committees regularly to redraft the syllabus; are constrained to tap academic resources from within the State, and are not able to achieve satisfactory 'inter se' moderation in evaluation.

**What can be done?**

First, manpower planning should be systematised and a separate ministry should be created for personnel management. This Ministry should clearly lay out a five-year road map for recruitment so that State PSCs are able to notify and conduct the examination process.

Along the lines of the list amendment of the Constitution (1970), which raised the maximum age limit of the members of State PSCs from 60 to 62 years in order to attract meritorious and experienced civil servants, there is a need for another amendment. The minimum age for appointment as a member should be fixed at 55 and the maximum age at 65. The stipulation of minimum age will enable State PSCs to benefit from the experience of senior civil servants who have retired at 60 for a longer period than under the existing provisions.

This amendment could also specify the necessary qualifications that members need in order to be appointed. For example, in order to be an 'official' member, experience as Secretary to a State government or a post equivalent to this rank should be stipulated while for 'non-official' members 10 years of practice in a recognised profession like law, medicine, or engineering should be stipulated. A mandatory pre-consultation with the leader of the Opposition before appointment may be considered for non-official members. Thus, a State wide panel of eminent people – those with high standing, integrity, merit and independence – should be constituted and periodically updated.

Secondly, the syllabus should be revised periodically, keeping in view the

**changing academic scenario and the syllabus for examinations as stipulated by the UPSC. Every proposal for revision should be placed in the public domain and changes can be made after public consultation. Knowledge on State specific areas like regional history, regional economy and regional geography, in which the availability of faculty is limited, should be tested in the objective type format so that there would be no scope for complaint on the grounds of asymmetry of information and value laden correction. Thus, while the preliminary examination may continue in the objective format, the main examination should be a mixture of objective and subjective papers. The process of translation of the questions from English to the regional language should not only involve technology for secrecy but also the human element so that the right meaning is conveyed. Care should be taken to regularly change the pattern of questions so that the role of AI-chat bots, as a source of information for formulating answers, is effectively countered.**

Finally, the Secretary of the State PSCs should be a senior officer with prior experience as either Commissioner of School Education or Secretary of the Board of Intermediate education to enable effective supervision of the examination branch of the Commission. Transparency and confidentiality should be balanced on the lines of the UPSC.

If these changes are effected, one would have vibrant Public Service Commissions at the State level on par with the Union Public Service Commission.

*The writer is the Founder Director of Brain Tree IAS Hyderabad and has been engaged in teaching public administration for the last 35 years.*

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मोटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने पीएससी को कैसे आकार दिया

- भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, भारतीयों ने सिविल सेवाओं में योग्यता-आधारित प्रवेश और राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा की मांग की।
- मोटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और सेवा मामलों के लिए एक स्थायी, राजनीतिक रूप से तटस्थ निकाय स्थापित करने की सिफारिश की।
- इसके आधार पर:

- संघ के लिए 1926 में पहला लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतों के लिए पीएससी बनाए।
- संविधान ने इस प्रणाली को जारी रखा, हमें अनुच्छेद 315-323 के तहत यूपीएससी और राज्य पीएससी दिए।

## राज्य पीएससी ट्रस्ट की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं?

### 1. नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप

- यूपीएससी के विपरीत, राज्य पीएससी राजनीतिक रूप से आसमाटिक वातावरण में काम करते हैं।
- पारंपरिक मानदंड-आयु, योग्यता, अखंडता-को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- "खराब प्रणाली" के परिणामस्वरूप नियुक्तियों में अनुभव या तटस्थता की कमी होती है।

### 2. खराब जनशक्ति योजना

- राज्यों के पास कामक प्रबंधन के लिए कोई समपत मंत्रालय नहीं है।
- रिक्तियां अनियमित, अप्रत्याशित होती हैं और अक्सर निम्न कारणों से विलंबित होती हैं:
  - वित्तीय बाधाएं
  - सेवानिवृत्ति की आयु का तदर्थ विस्तार
  - कार्यबल योजना का अभाव
- यह परीक्षा कैलेंडर को असंगत बनाता है।

### 3. कमजोर परीक्षा प्रक्रियाएं

- पाठ्यक्रम समय-समय पर अद्यतन नहीं किए जाते हैं।
- पैटर्न या सामग्री की समीक्षा करने के लिए समितियां दुर्लभ हैं।
- सीमित शैक्षणिक पूल- राज्य पीएससी अक्सर केवल स्थानीय विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं।
- उचित अंतर-संयम की कमी के कारण मूल्यांकन प्रभावित होता है।
- की जटिल गणना:
  - ऊर्ध्वाधर आरक्षण,
  - क्षैतिज आरक्षण,
  - और क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कोटा मुकदमेबाजी की ओर ले जाता है।

#### 4. बार-बार कानूनी चुनौतियाँ

- प्रश्न पत्रों, उत्तर कुंजी, अनुवाद, आरक्षण आवंटन और स्कोरिंग में त्रुटियाँ उम्मीदवारों को अदालतों में धकेल देती हैं।
- नतीजा: भर्ती वर्षों से अटकी रहती है → युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती है → विश्वास का क्षरण होता है।

#### कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (एमओपीपीजी एंड पी) की भूमिका

- केंद्र सरकार द्वारा 1985 में बनाया गया।
- प्रबंधन:
  - कार्मिक नीति
  - प्रशिक्षण (डीओपीटी)
  - शिकायत
  - पेंशन
- मंत्रालयों द्वारा नियमित रिक्ति रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है, जिससे यूपीएससी को प्रतिवर्ष, सुचारू रूप से और समय पर परीक्षा आयोजित करने में मदद मिलती है।
- राज्य स्तर पर इसी तरह की संस्थागत क्षमता का अभाव राज्य पीएससी की गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

#### क्या आवधिक पाठ्यक्रम की समीक्षा आवश्यक है?

हाँ बिल्कुल।

यूपीएससी ने निम्नलिखित समितियों के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन किया:

- सिविल सेवक
- शिक्षाविदों
- विषय विशेषज्ञ
- सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि

#### आवधिक संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- शैक्षणिक विषय विकसित होते हैं
- समकालीन मुद्दों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए
- पुरानी सामग्री परीक्षा को अप्रासंगिक बनाती है
- संशोधन की कमी से दोहराव, पूर्वानुमानित पैटर्न होते हैं

- यह अलग-अलग प्रश्न प्रारूपों को बदलकर AI उपकरणों के दुरुपयोग का मुकाबला करने में मदद करता है राज्य पीएससी में ऐसी समितियों की कमी है, जिससे पाठ्यक्रम स्थिर हो जाता है और त्रुटियां बढ़ जाती हैं।

## किन सुधारों की आवश्यकता है?

### 1. संरचनात्मक सुधार

#### A. कार्मिक प्रबंधन के लिए समर्पित राज्य मंत्रालय

- यूनियन डीओपीटी के समान।
- 5 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार करना चाहिए।
- नियमित रिक्ति सूचनाएं सुनिश्चित करें।

#### B. पीएससी सदस्यता पर संविधान संशोधन

- 41वें संशोधन (1976) ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी।
- एक नया संशोधन हो सकता है:
  - न्यूनतम आयु 55 वर्ष निर्धारित करें
  - अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित करें
  - आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करें
  - "आधिकारिक" और "गैर-आधिकारिक" सदस्य पात्रता को परिभाषित करें
  - विपक्ष के नेता के साथ परामर्श

यह अनुभवी सिविल सेवकों को आकर्षित करेगा और राजनीतिक नियुक्तियों से बचेगा।

### 2. प्रक्रियात्मक सुधार

#### A. आवधिक पाठ्यक्रम संशोधन

- हर 3-5 साल में समीक्षा की जानी चाहिए।
- परिवर्तनों को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक परामर्श।
- व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए राज्य-विशिष्ट विषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था) के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण।

#### B. अनुवाद सटीकता में सुधार करें

- प्रौद्योगिकी और मानव संपादन को मिलाएं।
- क्षेत्रीय भाषाओं में अंग्रेजी प्रश्नों के खराब अनुवाद से कई त्रुटियां उत्पन्न होती हैं।

**C. वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक पत्रों का मिश्रण**

- प्रीलिम्स पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण →
- मुख्य → उद्देश्य + वर्णनात्मक का मिश्रण यह विश्लेषणात्मक कठोरता को बनाए रखते हुए मूल्यांकन पूर्वाग्रह को कम करता है।

**D. मजबूत मॉडरेशन और मूल्यांकन प्रणाली**

- यूपीएससी-शैली इंटर-एसई मॉडरेशन।
- स्थानीय प्रभाव को कम करने के लिए पूरे भारत के बाहरी विशेषज्ञों का उपयोग करें।

**E. प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना**

- पीएससी सचिवों को पूर्व परीक्षा प्रशासन अनुभव (जैसे, स्कूल शिक्षा आयुक्त) के साथ वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए।

**F. गोपनीयता के साथ संतुलित पारदर्शिता**

- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
- वास्तविक समय अपडेट
- स्पष्ट शिकायत निवारण तंत्र

**आगे की राह**

- राज्य पीएससी की विश्वसनीयता के संकट के लिए तत्काल राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
- सुधारों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, न कि पीएससी के अलग-अलग अध्यक्षों पर निर्भर होना चाहिए।
- राज्य की स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए समान राष्ट्रीय मानक (न्यूनतम पात्रता, संयम, मूल्यांकन मानदंड) विकसित किए जा सकते हैं।

**समाप्ति**

राज्य पीएससी की कल्पना यूपीएससी की तरह राजनीतिक दबावों से अछूते योग्यता के स्तंभों के रूप में की गई थी। हालांकि, संरचनात्मक कमजोरियों, असंगत जनशक्ति योजना, राजनीतिक नियुक्तियों और पुरानी प्रक्रियाओं ने उनकी विश्वसनीयता को कम कर दिया है। व्यवस्थित सुधारों के साथ - संरचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक - राज्य पीएससी एक बार फिर भरोसेमंद संस्थानों के रूप में उभर सकते हैं जो भारत में प्रभावी शासन के लिए आवश्यक समय पर, पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रदान करते हैं।

**UPSC Mains Practice Question**

**प्रश्न:** राज्य लोक सेवा आयोगों के आसपास विश्वास की कमी संरचनात्मक खामियों और प्रक्रियात्मक कमजोरियों दोनों का परिणाम है। आलोचनात्मक जांच करें। (150 शब्द)

The letter has won but the spirit has not lost

The Republic of India has had 15 Presidents over 16 presidencies, its inaugural President, Dr. Rajendra Prasad having served two terms. Of the number of Governors appointed since 1947, the figure is too large to be counted.

The holders of these two high offices can do great good, sometimes not a little harm and very or most often, prefer an almost Advaitic selflessness that leaves no mark whatever – a self-protecting mechanism. It is better to be not remembered at all than remembered negatively. I have often wondered why these high functionaries, when they are males as they invariably are, carry pens in the pockets of their coats. The pen is almost a piece of their essential 'getting ready'-ness. It makes them seem ever-ready to sign the paper put up to them, wherever they are.

The master cartoonist, Abu Abraham, immortalised the 1975 moment when the then President signed the proclamation of the national emergency by a searing cartoon that showed him signing the paper when it was brought to him (this time with the stylus) at a very odd moment. Signatures can be affixed all too easily, when what is required is saying, 'No, very sorry, but no.' The reason may be plain gratitude for being where the Excellency wants to be.

Equally, when a signature is declined not out of genuine reservations but out of bias, an Abu Abraham or an R.K. Laxman is needed to depict the scene. Assents when given in fear or refused out of bias are infractions of Constitutional responsibility.

Reflections from the past

As one who knows that sometimes a signature (and more) can be affixed by a President on his own, without 'aid or advice' and without a care on whether what he was doing would 'go down well or not', I must recall here President R. Venkataraman (his years in office: 1987-92) and President K. R. Narayanan (years in office: 1997-2002). The pen was used by RV, confidently. It was used by KRN, independently. No cabinet as much as whispered disquiet. Morality was not coy with them, nor fairness halting.

The Prime Ministers RV's term coincided with – Rajiv Gandhi, V.P. Singh and Chandra Shekhar – were all strong-willed men but they were first-time incumbents of their pivotal office while RV's experience of political and constitutional office was infinitely bigger. It was natural that they deferred to him when on Bills or other recommendations he had a view contrary to the cabinet's; he put it across to them in one-on-one confidential discussions, that being his way. The fourth Prime Minister who overlapped with RV, P.V. Narasimha Rao, thought-partnered him more than he did his own cabinet colleagues. There was no scope for friction.

In 1997, the Union Cabinet headed by Prime



Gopal Krishna Gandhi

was Secretary to the President, and a Governor of West Bengal and Bihar

In the 16th Presidential Reference, the top court has upheld the letter and the spirit of the Constitution

Minister I.K. Gujral recommended to KRN the dismissal of the Bharatiya Janata Party (BJP) government in Uttar Pradesh headed by Kalyan Singh. KRN's world view and that of the BJP did not match. But he was the President of India, not just a resident of Rashtrapati Bhavan, answerable to the values of the Constitution. He did not agree with the recommendation of dismissal and sent it back for reconsideration. The recommendation did not come back.

By 1998, the BJP was in power at the Centre and the newly appointed Governor of Bihar recommended that the government of Rabri Devi be dismissed and President's Rule imposed under Article 356 of the Constitution of India. The Governor had sent what was claimed to be a fool-proof case showing financial mismanagement and poor law and order markers. KRN demurred, and sent the recommendation back. Prime Minister A.B. Vajpayee's cabinet did not repeat the recommendation. KRN's action in returning these recommendations had no politics to it. Zero. It had only fairness, Constitutional fairness. It had only morality, Constitutional morality. Fairness and morality are unmistakable. As are their opposites.

RV and KRN could be frank with the government when frankness was called for and they were not misunderstood for the government knew that the frankness came from a desire to caution and correct, not to criticise.

'Alert and alive'

Presidents and Governors are meant to be men and women with minds that are alert and alive to the letter of the Constitution and to its spirit in an evolving nation. They should see that recommendations made to them adhere to the letter, knowing that the letter can be used sometimes to subvert the spirit – an irony that the framers of the Constitution could not have anticipated. Would Babasaheb Ambedkar have thought that could have happened? The Constitution of India has been made by honest intentions for honest actuation.

No file was held by RV and KRN for more than a few days. They did not have to be detective-presidents. No delay was orchestrated during which confabulations could be held, and opinions sought in huddles, and given in whispers. No pocket was deepened for a pocket-veto to be exercised.

But their sense of Constitutional morality and fairness did not make them look out for flaws or faults or fallibilities as a full-time occupation, 24x7.

The President and Governors are neither robots, nor are they ring-masters. They are not inert rubber stamps that are pressed gently or not-so-gently onto any parchment that the government of the day places before them; they would make laughing stocks of themselves if they

were that. Nor are they pens that can choose any colour of ink or any vocabulary of their choice when expressing a Constitutional view.

Conservative and realistic

The 'answers' of the five-judge Bench headed by the Chief Justice of India (CJI) B.R. Gawai, and including CJI-designate Surya Kant, to President Droupadi Murmu's 16th Presidential Reference is imbued with this verity. The Bench has said that Governors cannot have a date-line fixed by the Supreme Court of India for their study of Bills – upholding the letter of the Constitution. The Bench has also said unambiguously that 'evasive inaction' is not 'on' either – upholding the spirit of the Constitution.

In saying the former, the Bench has been conservative. In saying the latter, it has been realistic. The Bench has made it clear that it knows that action and inaction by Governors may not be because they are studious and industrious but because they may be politically predisposed. The answers of the judges have said that no calendar can be hung on a Governor's wall that says 'This is your deadline'.

Their answers have also placed a clock on their desk that ticks loud and clear and has an informal alarm that can ring if the 'study' has prolonged beyond normal study hours, leaving it open for the delay to be raised in court.

The Constitution of India, especially in matters concerning Centre-State relations – or to put it differently, on matters affecting India's federal polity – takes two to work it, but just one, on either side, to wreck it. Ultimately, the working of a Constitutional arrangement depends on the two – legislature and the Governor/President – playing their roles with respect for the Constitution and for each other.

It is remarkable that the five judges unequivocally declined to school either side, or to assume the role of tutor. They have given neither side victory or defeat. The letter of the law has won, but the spirit of the law has not been defeated. In what is an opinion, not an order (for they were not handling an appeal), they have said what is exactly right: the Supreme Court should not, will not, say how a President or Governor should or should not act. That would amount to 'clutching at a jurisdiction' (a favourite phrase of RV's) which is not their's.

Has the Bench done an exercise in balancing? It has not. It has done an exercise for balance between the power to do right and the right way to do it.

The Indian polity needs to be run not by power games played by adroit players. It needs to be governed by men and women who, when in high office, rise above their limitations. Some incumbents make their offices great, some offices make their incumbents great. The tragedy, as the judges have seen, is that the opposite is equally true.

GS. Paper 2 भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question : का अक्षर सशक्त हो सकता है, लेकिन इसकी भावना मार्गदर्शन करती है। राज्यपालों की भूमिका के संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि भारत के संघीय संतुलन के लिए संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक तटस्थता कैसे आवश्यक हैं। (250 शब्द)

**संदर्भ:**

विधेयकों को रोकने, देरी करने या वापस करने में राज्यपालों की शक्तियों के बारे में 16वें राष्ट्रपति के संदर्भ पर हाल ही में पांच न्यायाधीशों की पीठ की राय ने भारतीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण बहस को फिर से जीवित कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के पत्र को यह दोहराते हुए बरकरार रखा कि राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए न्यायिक समय सीमा नहीं दी जा सकती है, इसने इस बात पर भी जोर दिया कि अनिश्चितकालीन 'टालमटोल निष्क्रियता' असंवैधानिक है, जो सहकारी संघवाद की भावना को संरक्षित करती है।

पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ऐतिहासिक उपाख्यानों का उपयोग करके इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे महान संवैधानिक पदाधिकारियों- जैसे आर. वेंकटरमन (आरवी) और के.आर. नारायणन (के.आर.एन) ने निर्णय लेने में संवैधानिक नैतिकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता को संतुलित किया। वह राजनीतिक प्रवृत्ति, देरी और संवैधानिक पदों के दुरुपयोग की वर्तमान प्रवृत्तियों के साथ उनके दृष्टिकोण की तुलना करता है।

**लेख में उठाए गए प्रमुख मुद्दे****1. राष्ट्रपतियों और राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका**

- उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की अक्षरशः और भावना दोनों के प्रति "सतर्क और जीवित दिमाग" के साथ कार्य करें।
- उन्हें बनने से बचना चाहिए:
  - रबर स्टैम्प (आँख बंद करके सहमति)
  - रिंगमास्टर्स (अपने अधिकार से अधिक)
  - केंद्र या किसी विशेष पार्टी के राजनीतिक एजेंट।

**2. संवैधानिक नैतिकता की ऐतिहासिक मिसालें****(a) राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन (1987-92)**

- कैबिनेट की सिफारिशों पर सवाल उठाने या वापस करने की शक्ति का प्रयोग किया।
- बिना किसी संघर्ष या देरी के प्रधानमंत्रियों के साथ स्पष्ट संचार।
- टकराव के बिना स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया।

**(b) राष्ट्रपति के. आर. नारायणन (1997-2002)**

- भाजपा के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद कल्याण सिंह यूपी सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश को वापस कर दिया।
- अनुच्छेद 356 के तहत राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करने की बिहार राज्यपाल की सिफारिश को लौटाया।
- कार्रवाई पूरी तरह से संवैधानिक निष्पक्षता पर आधारित थी, राजनीति पर नहीं।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे संवैधानिक पद स्वतंत्रता और अखंडता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

### 3. 16वें राष्ट्रपति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कोर्ट ने क्या कहा

- विधेयकों का अध्ययन करने के लिए राज्यपालों/राष्ट्रपतियों पर कोई निश्चित समय-सीमा नहीं लगाई जा सकती है।
- लेकिन अनिश्चितकालीन देरी या "टालमटोल निष्क्रियता" असंवैधानिक है।
- अदालतें सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करेंगी कि राज्यपालों को कैसे कार्य करना चाहिए।
- निर्णय संतुलित करता है:
  - संवैधानिक रूढ़िवाद: पाठ का सम्मान करना
  - व्यावहारिक यथार्थवाद: राजनीतिक दुरुपयोग को स्वीकार करना

### अदालत ने अनिवार्य रूप से क्या किया

- न तो राज्यों को और न ही राज्यपालों को "जीत" दी।
- राज्यपाल के आचरण पर एक अनौपचारिक घड़ी लगाई।
- पुष्टि की कि:
  - कानून का पत्र संरक्षित है
  - संविधान की भावना अपराजित है

### महत्वपूर्ण विश्लेषण

#### 1. संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण

- निर्वाचित राज्य सरकारों और नियुक्त राज्यपालों के बीच मतभेद बढ़ रहा है।
- विधेयकों को मंजूरी देने में लंबी देरी से यह कमज़ोर होता है:
  - लोकतंत्र में विधायी सर्वोच्चता
  - संघीय संतुलन
  - जनता का जनादेश

#### 2. न्यायिक विनम्रता बनाम न्यायिक जिम्मेदारी

न्यायालय:

- अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने से बचा गया।
- फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संवैधानिक नैतिकता उच्च पदों के कामकाज का मार्गदर्शन करती है। यह दृष्टिकोण पुष्ट करता है:
- शक्तियों का पृथक्करण
- संघवाद की भावना
- टकराव के बिना जांच करता है

### 3. संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता

- आंबेडकर ने चेतावनी दी कि अगर अच्छे इरादे से काम नहीं किया गया तो एक अच्छा संविधान अप्रभावी हो सकता है।
- लेख इस बात को प्रतिध्वनित करता है: "संविधान ईमानदार कार्यों के लिए ईमानदार इरादों से बनाया गया है।

आज का संकट कानून के बारे में कम और राजनीतिक संस्कृति और नैतिक जिम्मेदारी के बारे में अधिक है।

### 4. सहकारी संघवाद के लिए प्रासंगिकता

- बिलों को स्वीकार करने में राज्यपालों की देरी संघीय स्थिरता को कमजोर करती है।
- न्यायालय का मार्गदर्शन सुनिश्चित करता है:
  - कोई मनमाना हस्तक्षेप नहीं
  - कोई विधायी पक्षाघात नहीं
  - देरी को चुनौती देने के लिए एक तटस्थ तंत्र

### 5. आरवी और केआरएन से सबक

- संवैधानिक नैतिकता व्यक्तिगत है, पाठ्य नहीं।
- शत्रुता के बिना स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है।
- उच्च कार्यालयों की आवश्यकता:
  - अखंडता
  - बुद्धिमानी देखिए।
  - निष्पक्षता
  - जरूरत पड़ने पर 'नहीं' कहने का साहस

### समाप्ति

सुप्रीम कोर्ट की राय भारत के संवैधानिक ढांचे की संतुलित पुष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की मूल भावना दोनों को बनाए रखते हुए, यह संघवाद को राजनीतिक विकृतियों से बचाता है। गोपालकृष्ण गांधी के विचार हमें याद दिलाते हैं कि एक संवैधानिक लोकतंत्र का स्वास्थ्य अंततः न केवल कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है, बल्कि उच्च पद पर आसीन लोगों के नैतिक आचरण पर भी निर्भर करता है।

जैसे-जैसे भारत की राजनीति अधिक जटिल और विवादित होती जा रही है, ऐसे राष्ट्रपतियों और राज्यपालों की आवश्यकता है जो राजनीति से ऊपर उठते हैं और संवैधानिक नैतिकता को अपनाते हैं, तत्काल और अपरिहार्य दोनों हैं। न्यायालय ने एक रेखा खींची है - कठोर नहीं बल्कि दृढ़ - यह सुनिश्चित करते हुए कि संवैधानिक प्राधिकरण कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे कभी भी पूर्वाग्रह या निष्क्रियता के साथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।